**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding drinking water, sewerage and storm water management system in Delhi-laid.

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):** जल ही जीवन है, पानी की बूंद बूंद कीमती है । दिल्ली सरकार ने 2014 में कहा था कि 5 साल के अंदर हर घर में पाइप से पानी पहुंचाएंगे, फिर 2015 में कहा गया कि 5 साल में पाइप लाइन बिछा के हर घर में पानी आएगा और फिर 2016 में कहा गया कि दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर के अंदर पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचेगा और फिर 2019 में आश्वासन दिया गया कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी मुहैया करायेंगे । जबकि सरकार का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में जीएसटी लागू करने के कारण 39 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 69 हजार करोड़ रुपये के करीब हो गया । 2014 में क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन व पीने के पानी की पाइप लाइन डालनी थी इनके वर्क एक्शन प्लान व टेंडर 5 सितम्बर 2014 से पूर्व आ गए थे, जो बोर्ड मीटिंग के लिए प्रस्तावित थे । मेरे पास मुख्य सचिव व सीओ, ऑफिस मिनट की कॉपी है । जल बोर्ड के उन कार्यों का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पालम, साधनगर क्षेत्रों में जो सीवर लाइन डाली जा रही या डाली गई कैसे काम किया गया है उसकी जांच हो । ठेकेदारों से कथित मिलीभगत करके जनता का करोड़ों रूपया बर्बाद किया जा रहा है । पहले तो सीवर लाइन चालू नहीं हुई अगर कहीं हुई भी तो काम सही ढंग से नहीं किया गया । क्योंकि जो सीवर की लाइन डाली गई मेन होल कच्चे छोड़ दिए गए । पैड भी पक्के नहीं किए जिस कारण गंदा पानी जमीन में जा रहा है व कहीं कहीं ओवर फ्लो से साइड में घरों में फर्श को तोड़कर ऊपर उबल रहा है । गन्दा पानी जमीन को

दूषित तो कर ही रहा है बरसात के समय में पानी का दबाव बढ़ने से कालोनी वासियों के घरों में वह पानी फर्श से बैक मार रहा है । क्योंकि सड़क तो ऊपर से पक्की हो गई, जिस कारण लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़

रहा है, बीमारी फैलने का डर है । इसलिए शहरी विकास मंत्रालय व जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि इनकी जांच कराएं और जनता के करोड़ों रुपए बचाकर दोषियों को सजा दिलाई जाए ।